

प्रेषक,

डा0 एस0एस0 सन्धू,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

उप निदेशक,
राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड,
रूड़की-हरिद्वार।

औद्योगिक विकास अनुभाग-1

देहरादून: दिनांक: 19 जनवरी, 2007

विषय: राजकीय मुद्रणालय की आवासीय कालोनी में नवनिर्मित आवासीय भवनों की खाली जगह का भराव एवं मुख्यद्वार-पुराने भवनों से गुजरती हुई नये भवनों तक सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 4185/स्था0 दिनांक: 12.12.2006 के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु राजकीय मुद्रणालय रूड़की के आयोजनागत पक्ष के 04-राजकीय मुद्रणालय के भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार, 24-वृहत् निर्माण कार्य योजनान्तर्गत राजकीय मुद्रणालय की आवासीय कालोनी में नवनिर्मित आवासीय भवनों की खाली जगह का भराव हेतु रू0 5.60 लाख एवं मुख्यद्वार से पुराने भवनों से गुजरती हुई नये भवनों तक सड़क निर्माण हेतु रू0 14.24 लाख कुल रुपये 19.84 लाख की लागत के आगणनों के विपरीत टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरान्त कमशः संस्तुत रू0 14.00 लाख एवं रू0 5.55 लाख कुल रू0 19.55 लाख (रुपये उन्नीस लाख पचपन हजार मात्र) की धनराशि की लागत के आंगणन पर प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि आपके निर्वर्तन पर इस आशय से रखी जा रही है कि व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है तथा इस संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/आदेशों का कड़ाई से अनुपालन किया जाय। यह आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से वित्तीय नियमों का उल्लंघन होता हो यह करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका/बजट मैनुअल के नियमों का पालन भी सुनिश्चित किया जाय। उक्त धनराशि का उपयोग भवन निर्माण/आवास संबंधित परिव्यय के अनुरूप ही किया जायेगा।

3- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम अधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जाय।

4- कार्य पर उतना ही व्यय किया जाय जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृति नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जाय।

5- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएं तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।

6- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भाँति निरीक्षण उच्चाधिकारियों/भूगर्भवेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात् स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।

- 7- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाय एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाय।
- 8- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जाय, तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जाय।
- 9- वर्षान्त तक स्वीकृत की गयी धनराशि के विपरीत व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं योजना की वित्तीय एवं भौतिक प्रगति का विवरण शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। व्यय के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रहती है तो दिनांक: 31.03.2007 तक शासन को समर्पित किया जायेगा। व्यय उन्हीं योजना/कार्यों पर किया जाय जिन कार्यों हेतु यह स्वीकृत किया जा रहा है।
- 10- उपरोक्त धनराशि आहरित कर सम्बन्धित निर्माण एजेंसी उत्तर प्रदेश राजकीय निर्माण निगम लि०, रुड़की को आवश्यकतानुसार उपलब्ध कराई जायेगी। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता के लिए सम्बन्धित निर्माण एजेंसी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 11- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के अनुदान संख्या-23, मुख्य लेखाशीर्षक 4058-लेखन सामग्री तथा मुद्रण पर पूँजीगत परिव्यय, 00-आयोजनागत, 103-सरकारी मुद्रणालय, 04-राजकीय मुद्रणालय के भवनों का निर्माण/जीर्णोद्धार-00, 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 12- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 2079/XXVII(2)/2006 दिनांक 17 जनवरी, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(डा० एस०एस० सन्धू)
सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 5319(1)/VII-1-06/15 रा०मु०/04, तददिनांकित।
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्य हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
2. वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, रुड़की-हरिद्वार।
3. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
4. निजी सचिव-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
5. अपर सचिव, वित्त (बजट), उत्तराखण्ड शासन।
6. निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय उत्तराखण्ड, देहरादून।
7. अपर निदेशक, राजकीय मुद्रणालय उत्तराखण्ड, रुड़की-हरिद्वार।
8. निदेशक, एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
9. वित्त अनुभाग-2
10. गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,

(डा० एस०एस० सन्धू)
सचिव।

प्रेषक,

आर0के0 चौहान,
अनुसचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तरांचल, हल्द्वानी,

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून : दिनांक: 23 दिसम्बर, 2006

विषय: राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एकेश्वर, अमोठा के आवासीय /अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्रांक 4306-08/डीटीईयू/भवन/अमोठा/06, दिनांक 28-10-2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, एकेश्वर, अमोठा के आवासीय/अनावासीय भवनों के निर्माण हेतु कार्यदायी संस्था उत्तरांचल पेयजल निगम इकाई-श्रीनगर द्वारा प्रस्तुत रुपये 132.30 लाख के आगणन के सापेक्ष टी0ए0सी0 द्वारा परीक्षणोपरांत संस्तुत रुपये 107.74 लाख के आगणन की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए संस्तुत धनराशि के सापेक्ष वित्तीय वर्ष 2006-07 में कुल रुपये 50 लाख (रुपये पचास लाख मात्र) की धनराशि को व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितांत आवश्यक है, मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3- स्वीकृत धनराशि का आवंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने के लिये बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। व्यय उसी मदों/प्रयोजन में किया जायेगा, जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है। व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

4- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु संबंधित निर्माण एजेंन्सी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगी।

5- कार्य करते समय टैण्डर आदि विषयक विषयों का भी अनुपालन किया जायेगा।

6- कार्य करने के पूर्व किसी तकनीकी अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो तो वो प्राप्त करके ही कार्य प्रारम्भ किया जायेगा।

- 7- कार्य इसी लागत में पूर्ण कर लिया जायेगा और यदि विलम्ब या अन्य कारणों से इसकी लागत में बढ़ोत्तरी होती है तो उसके लिये कोई अतिरिक्त धनराशि देय नहीं होगी।
- 8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक: 31.03.2007 तक पूर्ण उपयोग कर कार्य की वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को प्रस्तुत कर दिया जायेगा।
- 9- टी0ए0सी0 के निम्न बिन्दु 1 से 9 तक में दर्शायी गयी शर्तों/प्रतिबन्धों का पूर्ण रूप से नुपालन कराया जाये।
 - 1- आगणन में उल्लिखित दरों का विश्लेषण विभाग के अधीक्षण अभियन्ता द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों को जो दरें शिडयूल आफ रेट में स्वीकृत नहीं है अथवा बाजार भाव से ली गयी हो, की स्वीकृति नियमानुसार अधीक्षण अभियन्ता को अनुमोदन आवश्यक होगा।
 - 2- कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन/मानचित्र गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से प्राविधिक स्वीकृति प्राप्त करनी होगी, बिना प्राविधिक स्वीकृति के कार्य प्रारम्भ न किया जायें।
 - 3- कार्य का उतना ही व्यय किया जाये, जितना कि स्वीकृत नार्म है, स्वीकृत नार्म से अधिक व्यय कदापि न किया जायें।
 - 4- एक मुश्त प्राविधान को कार्य करने से पूर्व विस्तृत आगणन गठित कर नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति प्राप्त करना आवश्यक होगा।
 - 5- कार्य कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताएँ तकनीकी दृष्टि के मध्य नजर रखते एवं लोक निर्माण विभाग द्वारा प्रचलित दरों/विशिष्टियों के अनुरूप ही कार्य को सम्पादित कराते समय पालन करना सुनिश्चित करें।
 - 6- कार्य कराने से पूर्व स्थल का भली-भांती निरीक्षण उच्च अधिकारियों एवं भुगर्ववेत्ता के साथ अवश्य करा लें। निरीक्षण के पश्चात स्थल आवश्यकतानुसार निर्देशों तथा निरीक्षण टिप्पणी के अनुरूप कार्य किया जायें।
 - 7- आगणन में जिन मदों हेतु जो राशि स्वीकृति की गयी है, उसी मद पर व्यय किया जाये, एक मद का दूसरी मद में व्यय कदापि न किया जाये।
 - 8- निर्माण सामग्री को प्रयोग में लाने से पूर्व किसी प्रयोगशाला से टेस्टिंग करा ली जायें तथा उपयुक्त पायी जाने वाली सामग्री को प्रयोग में लाया जायें।
 - 9- जी0पी0डब्लू फार्म 9 की शर्तों के अनुसार निर्माण इकाई को कार्य सम्पादित करना होगा तथा समय से कार्य को पूर्ण न करने पर 10 प्रतिशत की दर से आगणन की कुल लागत का निर्माण इकाई से दण्ड वसूल किया जायेगा।
 - 10- मुख्य सचिव, उत्तरांचल के शासनादेश संख्या 2047.XIV-219 (2006) दिनांक 30.5.2006 द्वारा निर्गत आदेशों के कम में कार्य कराते समय अथवा आगणन गठित करते समय कड़ाई से पालन करने का कष्ट करें।
- 10- व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिनके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।
- 11- कार्य करते समय वित्तीय हस्तपुस्तिका, बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज रूल्स एवं मितव्ययता के संबंध में समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन किया जायेगा।

- 12- उक्त निर्माण कार्य की भौतिक प्रगति रिपोर्ट प्रत्येक माह शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
- 13- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु अनुदान संख्या-16 मुख्य लेखाशीर्षक-4216-आवास पर पुर्जीगत परिव्यय, 80-सामान्य, 001-निदेशन तथा प्रशासन, 07-राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों का सुदृढीकरण के सुसंगत मानक मद 24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 14- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: यू0ओ0: 754/XXVII(5)/2006, दिनांक: 19-दिसम्बर, 2006 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 1970(1)/VIII/75-प्रशि0/2006, तददिनांकित :-

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
- 2- आयुक्त, गढ़वाल मण्डल।
- 3- जिलाधिकारी, पौड़ी।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी, पौड़ी।
- 5- परियोजना प्रबन्धक, उत्तरांचल पेयजल निगम इकाई-1 श्रीनगर को संशोधित आंगणन की प्रति सहित।
- 6- वित्त अनुभाग-5
- 7- नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
- 8- एन0आई0सी0, सचिवालय, देहरादून।
- 9- निजी सचिव, मा0 श्रम मंत्री जी।
- 10- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन।
- 11- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

प्रेषक,

विजय कुमार ढोडियाल,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

विषय: सेन्टर ऑफ एक्सीलेंस योजना के तहत (75 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना) आयोजनागत पक्ष में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, युवक, देहरादून एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, काशीपुर के लिए अन्य व्ययों हेतु 17.6 लाख अवमुक्त करने के सम्बन्ध में।

देहरादून : दिनांक: 22 जनवरी, 2007

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 19706-07/डीटीईयू/0202/लेखा/सीओई0/2006-07, दिनांक 01-12-2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि राज्य में भारत सरकार के सहयोग से संचालित की जा रही सेन्टर आफ एक्सीलेंस योजना (75 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना) के अन्तर्गत भारत सरकार के पत्र संख्या : DGET-35(4)(20)/Other charges-Uttaranchal /2006-CPIU-PCT, Dated 30th Oct, 2006 के द्वारा राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, युवक, देहरादून एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, काशीपुर के लिए अन्य व्ययों हेतु केन्द्रांश के रूप में अवमुक्त रुपये 13.2 लाख तथा उक्त केन्द्रांश के सापेक्ष राज्यांश रुपये 4.4 लाख इस प्रकार कुल रुपये 17.60 लाख (रुपये सत्रह लाख साठ हजार मात्र) धनराशि की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए उक्त धनराशि को व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निवर्तन पर रखी जा रही है, कि उक्त मद में आवंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आबंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3- व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएसएण्डडी की दरों अथवा शर्तों, टेण्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- उक्त धनराशि भारत सरकार के उपरोक्त समसंख्यक पत्र दिनांक 30-अक्टूबर, 2006 में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए व्यय की जाए।

5- उक्त धनराशि को 31/3/2007 तक पूर्ण व्यय करते हुये उपयोगिता तथा उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

१

6- उक्त धनराशि उन्ही मदों में व्यय की जाय जो मदें अन्य व्यय में भारत सरकार द्वारा अनुमोदित हैं, तथा उपरोक्त पत्र दिनांक 30-10-2006 में उल्लिखित हैं।

7- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु अनुदान संख्या-16 मुख्य लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार, 03-प्रशिक्षण-आयोजनागत-00, 003-दस्तकारों तथा पर्यवेक्षकों का प्रशिक्षण, 01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें, 0101-योजना आधुनिकीकरण एवं सुदृढीकरण (75 प्रतिशत के 0 स0) के अन्तर्गत मानक मद 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा। यह आबंटन निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के अधीन राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, युवक, देहरादून एवं राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, काशीपुर के लिए किया जा रहा है।

8- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 13/वित्त अनु0-5/2006, दिनांक: 12-जनवरी, 2007 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय

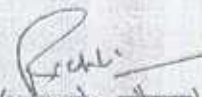
(विजय कुमार ढौडियाल)
अपर सचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 2183(1)/VIII/06-10-प्रशि0/2006, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून/उधमसिंह नगर।
- 3- अपर सचिव, वित्त-बजट।
- 4- निजी सचिव, मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 5- वित्त अनुभाग-5
- 6- नियोजन विभाग।
- 7- अनुसचिव, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को उनके पत्र दिनांक 30-10-06 के क्रम में सूचनार्थ।
- 8- एन0आई0 सचिवालय परिसर।
- 9- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,


(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

प्रेषक,

आर०के० चौहान,
अनुसचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

संख्या: 2184/VIII/11-सेवा०/2006

सेवा में,

निदेशक,
प्रशिक्षण एवं सेवायोजन,
उत्तराखण्ड, हल्द्वानी।

श्रम एवं सेवायोजन विभाग

देहरादून : दिनांक: 11, जनवरी, 2007

विषय: वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु सेवायोजन प्रखण्ड के अन्तर्गत आयोजनेत्तर पक्ष में टी.एस.पी. के अधीन संचालित योजनाओं हेतु अवचनबद्ध मदों में धनराशि अवमुक्त किए जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक आपके पत्र संख्या: 19708/डीटीईयू/लेखा/सेवा/बजट मांग/2006, दिनांक 1.12.2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्तीय वर्ष-2006-07 हेतु प्रशिक्षण एवं सेवायोजन विभाग के अन्तर्गत सेवायोजन प्रखण्ड में टी.एस.पी. के अधीन आयोजनेत्तर पक्ष में अवचनबद्ध मदों की धनराशि संलग्न-विवरणानुसार रुपये 2,25,000/- (रुपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र) की धनराशि के व्यय किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- उक्त धनराशि इस प्रतिबन्ध के साथ एवं शर्तों के अधीन आपके निर्वर्तन पर रखी जा रही है, कि उक्त मद में आबंटित सीमा तक ही व्यय सीमित रखा जाये। यहाँ यह भी स्पष्ट किया जाता है, कि धनराशि का आबंटन किसी ऐसे व्यय को करने का अधिकार नहीं देता है, जिसे व्यय करने से बजट मैनुअल या वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों या अन्य आदेशों का उल्लंघन होता हो। जहाँ व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, वहाँ ऐसा व्यय सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त करके ही किया जायेगा। व्यय में मितव्ययता नितान्त आवश्यक है, मितव्ययता के सम्बन्ध में समय-समय पर जारी शासनादेशों/अन्य आदेशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाये। व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा जिसके लिये यह स्वीकृत किया जा रहा है।

3- व्यय करते समय स्टोर परचेज रूल्स, डीजीएसएण्डडी, की दरों अथवा शर्तों, टेण्डर/कोटेशन आदि के विषयक नियमों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

4- कम्प्यूटर आदि का क्रय एन०आई०सी०/आई०टी० की संस्तुति अथवा उनके दिशा-निर्देशों का अनुपालन करते हुए किया जायेगा।

- 5- उक्त धनराशि को 31/3/2007 तक पूर्ण व्यय करते हुये उपयोगिता तथा उपभोग प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें ।
- 6- उक्त व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 हेतु अनुदान संख्या-31 मुख्य लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार के अन्तर्गत संलग्नक में उल्लिखित लेखाशीर्षक की सुसंगत मानक मदों के नामे डाला जायेगा । यह आबंटन निदेशक, प्रशिक्षण एवं सेवायोजन के अधीन समस्त कार्यालयों के लिए किया जा रहा है ।
- 7- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या: 07/वित्त अनु0-5/2006, दिनांक: 07-जनवरी, 2007 के अन्तर्गत प्राप्त उनकी सहमति से जारी किए जा रहे हैं ।

संलग्न : यथोपरि।

भवदीय

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

पृष्ठांकन संख्या: 2184(1)/VIII/11-सेवा0/2006, तददिनांक :

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 2- सम्बन्धित जनपद के कोषाधिकारी ।
- 3- अपर सचिव, वित्त-बजट ।
- 4- वित्त अनुभाग-5
- 5- नियोजन विभाग।
- 6- एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर।
- 7- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

(आर0के0 चौहान)
अनुसचिव।

शासनादेश संख्या: 2184 / VIII / 11-सेवा 0 / 2006, दिनांक: 11 जनवरी, 2007 का संलग्नक:
आयोजनेत्तर अनुदान संख्या: 31 धनराशि हजार रुपये में

मुख्य लेखाशीर्षक 2230-श्रम तथा रोजगार

02-रोजगार सेवायें

796-जनजातिय क्षेत्र उप योजना

02-कालसी देहरादून में जनजातिय के अभ्यर्थियों के लिए विशिष्ट रोजगार केन्द्र
आंबटित धनराशि

क्र०सं०	कोड / मद	
1.	04-यात्रा व्यय	10
2.	08-कार्यालय व्यय	20
3.	11-लेखन सामग्री / फार्म छपाई	10
4.	12-कार्यालय फर्नीचर / उपकरण	20
5.	26-मशीनें साज-सज्जा / उपकरण व संयंत्र	05
6.	27-चिकित्सा व्यय प्रतिपूर्ति	50
7.	45-अवकाश यात्रा व्यय	50
8.	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर कय	50
9.	47-कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी	10
योग :		225

(रुपये दो लाख पच्चीस हजार मात्र)


(आर०के० चौहान)
अनुसचिव।

प्रेषक,

संख्या: 860/IX/64/2006

एस0 रामास्वामी,
सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

प्रबंध निदेशक,
उत्तरांचल परिवहन निगम,
देहरादून।

परिवहन अनुभाग

देहरादून : दिनांक: 29 दिसम्बर, 2006

विषय: उत्तरांचल परिवहन निगम के अधिकारियों/कर्मचारियों को मंहगाई भत्ते के भुगतान के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक शासनादेश संख्या-184/IX/64/2006, दिनांक 21 मार्च, 2006 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासनादेश संख्या: 29/XXVII(7)/2006, दिनांक 26 अप्रैल, 2006 एवं शासनादेश संख्या: 29 (1)/XXVII (7) म0म0/2006, दिनांक 29 सितम्बर, 2006 द्वारा राज्य कर्मचारियों और सहायता प्राप्त शिक्षण एवं प्राविधिक शिक्षण संस्थाओं तथा शहरी स्थानीय निकायों के कर्मचारियों को समय-समय पर अनुमन्य किशतों को जोड़ने पर अंतिम रूप से कुल 79 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है। सुलभ संदर्भ हेतु उपरोक्त शासनादेशों की छाया प्रतियां संलग्न हैं, जिसके विपरीत परिवहन निगम के लिए अंतिम बार उक्त उल्लिखित शासनादेश संख्या: 184/IX/64/2006, दिनांक 21 मार्च, 2006 द्वारा 71 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ता अनुमन्य किया गया है।

2- वित्त विभाग द्वारा जारी शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2006 के क्रम में तथा उत्तरांचल परिवहन निगम के निदेशक मण्डल के अनुमोदन को दृष्टिगत रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त परिवहन निगम के कार्मिकों को उक्त उल्लिखित शासनादेश दिनांक 29 सितम्बर, 2006 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन शासनादेश निर्गत होने की तिथि से 79 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते का भुगतान किये जाने की निम्न प्रतिबन्धों के अधीन श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

(1) यह सुविधा उत्तरांचल परिवहन निगम के समस्त पूर्णकालिक कार्मिकों को इस शर्त के अधीन प्रदान की जाती है कि परिवहन निगम यह सुनिश्चित कर लें, कि इस हेतु जो

भी अतिरिक्त वित्तीय व्यय भार आयेगा उसको उनके द्वारा स्वयं अपने वित्तीय स्रोतों से वहन करना होगा। शासन द्वारा किसी भी प्रकार के भुगतान हेतु धनराशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी।

3- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 2011/वि0अनु0-2/2006, दिनांक 28 दिसम्बर, 2006 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

(एस0 रामास्वामी)
सचिव।

संख्या: 060(1)/ix/ 64 /2006 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तरांचल, ओबराय भवन माजरा रोड, देहरादून।
- 2- वित्त अनुभाग-2
- 3- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 4- गार्ड-फाईल।

आज्ञा से,


(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव।

AKW

प्रेषक,

दयाल सिंह नाथ
अपर सचिव
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

परिवहन आयुक्त,
उत्तराखण्ड 8, रामबाग
कावली रोड देहरादून ।

परिवहन अनुभाग

देहरादून दिनांक 19 जनवरी, 2007

विषय:- देहरादून के अन्तर्गत कुल्हान (करनपुर) में खसरा न0-2 क में परिवहन आयुक्त कार्यालय भवन आदि के निर्माण हेतु वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए एन.पी.वी. की धनराशि स्वीकृत किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-280/500/ix/2006 दिनांक 28 मार्च 2006 एवं वन विभाग के नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक के पत्रांक 1869/1 जी-1756 (देहरादून) दिनांक 21-12-2006 के क्रम में आपके पत्र संख्या-72/स्थापना/एक-7/2006, दिनांक 22 दिसम्बर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय, जनपद देहरादून के अन्तर्गत कुल्हान (करनपुर) में खसरा न0-2 क में परिवहन आयुक्त कार्यालय भवन निर्माण आदि के सम्बन्ध में वन भूमि के प्रत्यावर्तन के लिए एन.पी.वी. की धनराशि के भुगतान हेतु रु0 4,69,220/- (रुपये चार लाख उनहत्तर हजार दो सौ बीस मात्र) की धनराशि के व्यय की सहर्ष स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन प्रदान करते हैं।

2- स्वीकृत की जा रही एन.पी.वी. की धनराशि का बैंक ड्राफ्ट Compensatory Afforestation fund Uttaranchal A/c No CA 1594 Payable at New Delhi के नाम बनाकर नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग, इन्द्रानगर फारेस्ट कालोनी, देहरादून, उत्तराखण्ड को यथाशीघ्र उपलब्ध कराया जायेगा।

- 3- उक्त धनराशि का व्यय उसी कार्य के लिए किया जायेगा जिसके लिए यह स्वीकृत किया रहा है।
- 4- उक्त धनराशि को वन विभाग को अविलम्ब भुगतान कर उनकी अन्तिम अनापत्ति लेकर उक्त कार्य तत्काल प्रारम्भ करके इसकी मासिक वित्तीय व भौतिक प्रगति से शासन को भी अवगत कराया जायेगा।
- 5- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के अनुदान संख्या-24 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक 5055-सड़क परिवहन पर पूंजीगत परिव्यय-00-आयोजनागत-050-भूमि तथा भवन-03-परिवहन आयुक्त/जनपदीय कार्यालयों के अनावासीय भवन भूमि क्रय-00-24-वृहत निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।
- 6- यह आदेश वित्त विभाग के अ०शा०सं०- 2116/xxxvii(2)/ 07 दिनांक 18 जनवरी, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(दयाल सिंह नाथ)
अपर सचिव।

संख्या-44 (1)/ix ~~500~~ 2007 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय भवन माजरा रोड, देहरादून।
- 2- आयुक्त गढ़वाल मण्डल पौड़ी, उत्तराखण्ड।
- 3- नोडल अधिकारी एवं मुख्य वन संरक्षक, भूमि सर्वेक्षण निदेशालय, वन विभाग इन्द्रानगर फास्ट कॉलोनी देहरादून उत्तराखण्ड।
- 4- वरिष्ठ कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- निजी सचिव, मा० परिवहन मंत्री जी उत्तराखण्ड।
- 6- राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-2/नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(गरिमा रौकली)
उप सचिव

उत्तराखण्ड शासन
माध्यमिक शिक्षा अनुभाग-4
सं० 406 / xxiv-4/2007
देहरादून:दिनांक: 19 जनवरी, 2007

कार्यालय ज्ञाप

उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा अधिनियम, 2006 की धारा 5 एवं 6 (1) में की गई व्यवस्था के क्रियान्वयन के उद्देश्य से श्री राज्यपाल महोदय एतद्वारा उत्तराखण्ड विद्यालयी शिक्षा परिषद के निम्नवत गठन की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

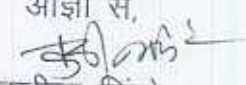
- | | |
|---|-------------|
| 1. निदेशक, विद्यालयी शिक्षा उत्तराखण्ड | पदेन सभापति |
| 2. निदेशक, प्राविधिक शिक्षा, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 3. प्राचार्य, महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स कालेज, देहरादून | सदस्य |
| 4. अपर निदेशक, राज्य शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 5. अपर शिक्षा निदेशक, विद्यालयी शिक्षा निदेशालय, उत्तराखण्ड | सदस्य |
| 6. सचिव, उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद रामनगर, नैनीताल | सदस्य सचिव |

एस.के. माहेश्वरी
सचिव।

संख्या 406 (1) / xxiv -4 / 2007 / तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- निजी सचिव, गा० मुख्य मंत्री जी / मा० शिक्षा मंत्री जी।
- 3- निदेशक विद्यालयी शिक्षा, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 4- समस्त जिलाधिकारी / कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- अपर निदेशक, एस०सी०ई०आर०टी० नरेन्द्र नगर, टिहरी।
- 6- अपर सचिव, उत्तराखण्ड शिक्षा एवं परीक्षा परिषद, रामनगर, नैनीताल।
- 7- अपर / संयुक्त शिक्षा निदेशक गढ़वाल मण्डल, पौड़ी / कुमाँयू मण्डल, नैनीताल।
- 8- समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 9- समस्त माननीय सदस्यगण।
- 10- वित्त विभाग / नियोजन प्रकोष्ठ।
- 11- एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 12- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(कवीन्द्र सिंह)
अनु सचिव।

प्रेषक,

उत्पल कुमार सिंह
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जड़ी-बूटी शोध एवं विकास संस्थान,
गोपेश्वर (चमोली)।

उद्घान एवं रेशम अनुभाग:-2

देहरादून: दिनांक 22 जनवरी, 2007

विषय: शासनादेश संख्या-849/XVI/05/10(2)/05, दिनांक 09, सितम्बर, 2005 द्वारा सृजित
अस्थाई पदों की निरन्तरता की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-359/ज0बू0सं0/कैम्प/2006-07/ दिनांक- 28, जुलाई, 2006 तथा पत्रांक-479/ज0बू0शो0/कैम्प/2006-07, दिनांक-09, नवम्बर, 2006 के सन्दर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री राज्यपाल महोदय भारत सरकार से सहयोग से स्थापित प्रयोगशाला एवं सगन्ध पादप केंद्र, सेलाकुई, देहरादून के कार्यों के सम्पादन हेतु निम्नलिखित अस्थाई पदों को दिनांक-01/03/2006 से दिनांक- 28/02/2007 तक अथवा उससे पूर्व जब तक इन्हें बिना पूर्व नोटिस के समाप्त न कर दिया जाय, निरन्तर चलते रहने की स्वीकृति सहर्ष प्रदान करते हैं।

क0सं0	पदनाम	वेतनमान	संख्या
1	2	3	4
1-	वैज्ञानिक-ई(गुणवत्ता नियंत्रण)	14300-18300	1
2-	वैज्ञानिक-ई (एग्रोनॉमी)	14300-18300	1
3-	वैज्ञानिक-सी (टैक्सोनॉमी)	10000-15200	1
4-	वैज्ञानिक बी- (प्रसार)	8000-13500	1
5-	वैज्ञानिक बी- (रसायन)	8000-13500	1
6-	तकनीकी सहायक	5500-9000	2
7-	तकनीकी सहायक	5500-9000	4
8-	लेखाकार	5000-8000	1
9-	आशुलिपिक/वरिष्ठ लिपिक	4000-6000	2
10-	कम्प्यूटर आपरेटर	3050-4590	1
	योग:-		15

- 2- उपर्युक्त पदधारकों को शासन द्वारा समय-समय पर अनुमन्य मंहगाई भत्ता तथा अन्य भत्ते प्राप्त होंगे।
- 3- उपर्युक्त पद प्रतिनियुक्ति अथवा सर्विस प्रोवाइडिंग एजेन्सी के माध्यम से भरे जायेंगे।
- 4- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय व्ययक के अनुदान संख्या-29 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म, 00-आयोजनागत, 119-बागवानी और सब्जियों की फसलें, 09-जड़ी-बूटी शोध संस्थान, 20-सहायक अनुदान/अंशदान/राजसहायता के नामे डाला जायेगा।
- 5- दिनांक-01, मार्च, 2007 से आगे की निरन्तरता हेतु प्रस्ताव 28, फरवरी, 2007 से पूर्व शासन को प्रस्तुत कर लिया जाय।
- 6- यह आदेश वित्त विभाग द्वारा दिनांक-12/01/2007 को प्रदत्त सहमति से निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव।

संख्या-1165/ XVI/ 06 / 10 (2) / 05, तददिनांकित।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण उद्यान भवन चौबटिया-रानीखेत।
- 3- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उत्तराखण्ड शासन।
- 4-नियंत्रक/प्रभारी अधिकारी, सगन्ध पादप केन्द्र, सेलाकुई, देहरादून।
- 5- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 6-गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एस0के0सिंह)

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
कृषि एवं विपणन अनुभाग-2
संख्या : 43/72(5)/XIII-II/2005
देहरादून : दिनांक : 22-जनवरी, 2007

संशोधन

समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों हेतु प्राप्त केंद्रांश के सापेक्ष राज्योंश अवमुक्त किये जाने विषयक शासनादेश संख्या 992/XIII-II/72(5)/2005 दिनांक 3.1.07 में जनपद के क्रमांक -6 पिथौरागढ़ (परियोजना प्रथम) (तृतीय किस्त) में राज्योंश की धनराशि रु0 9.5909 लाख के स्थान पर रु0 9.05909 लाख (रु0 नौ लाख पॉच हजार नौ सौ नौ मात्र) पढ़ा जाय।


2. शासनादेश संख्या : 992/XIII-II/72(5)/2005 दिनांक 3.1.07 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय।
3. शासनादेश संख्या : 992/XIII-II/72(5)/2005 दिनांक 3.1.07 की अन्य शर्तें और प्राविधान पूर्ववत् रहेंगे।


(उत्पल कुमार सिंह)
सचिव

संख्या : 43⁰⁷/XIII-II/72(5)/2005 दिनांकित

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. महालेखाकार, उत्तराखण्ड।
2. प्रमुख सचिव एवं आयुक्त वन एवं ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. आयुक्त, ग्राम्य विकास उत्तराखण्ड, पौड़ी।
4. सचिव, ग्राम्य विकास, उत्तराखण्ड शासन।
5. सचिव, कृषि, उत्तराखण्ड शासन।
6. सचिव, वित्त, उत्तराखण्ड शासन।
7. आयुक्त, गढ़वाल मण्डल पौड़ी/कुमायू मण्डल, नैनीताल।
8. जिलाधिकारी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़।
9. कोषाधिकारी, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़।
10. मुख्य परियोजना निदेशक, जलागम प्रबन्ध निदेशालय, देहरादून।
11. परियोजना निदेशक, जिला ग्राम्य विकास अभिकरण, चमोली, बागेश्वर, पिथौरागढ़।
12. निदेशक, भारत सरकार, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भूमि संसाधन विभाग, एन0बी0ओ0 बिल्डिंग, निर्माण भवन, नई दिल्ली।
13. बजट राजकोषीय नियोजन संस्थान निदेशालय, सचिवालय, देहरादून।
14. निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, देहरादून।
15. गार्ड फाईल।


(शैलेश कुमार पंत)
अनु सचिव

प्रेषक,

टी0के0 पन्त,
संयुक्त सचिव,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवामे,

मुख्य अभियन्ता स्तर-1,
लोक निर्माण विभाग,
देहरादून।

लोक निर्माण अनुभाग-2

देहरादून, दिनांक 22, जनवरी, 2007

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-07 में एन.पी.वी., भूमि प्रतिकर के भुगतान एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण आदि की प्रथम अनुपूरक माँग में प्राविधानित धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश सं0-2227/111(2)/06-19 (बजट)/2006 दिनांक 3 अगस्त, 2006 एवं संख्या- 224/111-2/06-06 (बजट)/2003 दिनांक 06 फरवरी, 2006 के सन्दर्भ में एवं वित्त अनुभाग-1 के पत्र सं0 1628(1)/XXVII (1)/2006 दिनांक 19 अक्टूबर, 2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि के अधिग्रहण एवं भूमि प्रतिकर के भुगतान के लिये प्रथम अनुपूरक माँग के अन्तर्गत रुपये 360542 हजार (रु0 छत्तीस करोड़ पाँच लाख बयालीस हजार मात्र) की व्यवस्था की गई है। जिसमें सचिवालय विस्तारीकरण हेतु अधिग्रहित भूमि के प्रतिकर भुगतान हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से आहरित रु0 6,05,42,000.00 (रु0 छः करोड़, पाँच लाख, बयालीस हजार रुपये मात्र) की धनराशि की प्रतिपूर्ति भी शामिल है। शासनादेश सं0 संख्या-224/111-2/06-06 (बजट)/2003 दिनांक 06 फरवरी, 2006 द्वारा देहरादून में सचिवालय के विस्तारीकरण हेतु उत्तर की ओर भूमि का अधिग्रहण हेतु राज्य आकस्मिकता निधि से अग्रिम के रूप में आहरित धनराशि रु0 6,05,42,229.00 (रु0 छः करोड़ पाँच लाख बयालीस हजार दो सौ उन्नीस मात्र) को सुम्माकित करते हुए प्रथम अनुपूरक माँग में व्यवस्थित धनराशि रु0 360542 हजार में से रु0 60542 हजार (रु0 छः करोड़ पाँच लाख बयालीस हजार मात्र) को समायोजित करते हुए अवशेष रु0 30.00 करोड़ (रु0 तीस करोड़ मात्र) की धनराशि व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- एन0पी0वी0 एवं भूमिप्रतिकर का भुगतान एवं क्षतिपूरक वृक्षारोपण के भुगतान वर्षवार वरियता के आधार पर चालू कार्य हेतु ही किया जायेगा। अर्थात् सबसे पुरानी देयता का भुगतान सबसे पहले तथा उसके बाद के वर्ष का उसके बाद तथा इसी वर्ष की सड़कों का सबसे अन्त में किया जायेगा, तथा वरियता के आधार पर जैसे-2 देयताओं का भुगतान किया जायेगा उसकी सूचना शासन को मासिक रूप से उपलब्ध कराई जायेगी। विभागाध्यक्ष के द्वारा उक्त देयों के भुगतान हेतु निर्वतन पर रखी जा रही धनराशि से परिपक्व दावों का भुगतान अपने स्तर से आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

3- भूमिप्रतिकर भुगतान में मा0 न्यायालयों एवं विधायिका में आश्वस्त किये गये प्रकरणों का भुगतान प्राथमिकता के आधार पर प्रथम वरीयता में किया जायेगा।

4- उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग एन.पी.वी. भुगतान हेतु वन विभाग को किया जाये।

5- जिलाधिकारी द्वारा निर्धारित दरों पर विभाग द्वारा भुगतान किया जायेगा तथा कय की गई भूमि का शीघ्र विभाग के नाम हस्तान्तरण कर राजस्व अभिलेखों में दर्ज किया जायेगा।

6- उक्त धनराशि को व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, वित्तीय हस्तपुस्तिका के नियमों का या अन्य सुसंगत आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा, तथा व्यय करने से पूर्व सक्षम अधिकारी का अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

7- स्वीकृत धनराशि का आहरण साख सीमा के माध्यम से आवश्यकतानुसार किया जायेगा।

8- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक 31.3.2007 तक पूर्ण उपयोग करके वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

9- यदि धनराशि स्वीकृत करने के बाद भी पूर्व के वर्षों की देयता रहती है और धनराशि शासन को समर्पित की जाती है तो इस हेतु उत्तरदायित्व का निर्धारण किया जायेगा। अतः स्वीकृत की जा रही धनराशि का समयबद्ध रूप से उपयोग व दायित्व विभागाध्यक्ष का ही होगा। स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय साख परिव्यय के अधीन, स्थापित नियमों एवं प्रक्रिया के अधीन ही सुनिश्चित किया जायेगा। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि सभी परिपक्व रखे प्रस्तर-2 की वरियता के अनुसार तत्काल भुगतान सुनिश्चित करके इसका मासिक व्यय विवरण भी शासन को उपलब्ध कराया जाय।

10- इस संबंध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-22 लेखाशीर्षक-5054 सड़कों तथा सेतुओं पर पूँजीगत परिव्यय 04-जिला तथा अन्य सड़के-आयोजनागत- 800-अन्य व्यय-05 सड़क/भवन/पुल आदि हेतु भूमि अधिग्रहण-00-24 वृहत्त निर्माण कार्य के नामें डाला जायेगा।

11- यह आदेश वित्त विभाग के अ.शा. सं०-16/XXVII(2)/07, दिनांक, 18 जनवरी, 2007 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय,

(टी०के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

संख्या- 167(1)/III(2)/06, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा प्रथम) ओबराय मोटर्स माजरा, देहरादून।
- 2- मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन।
- 3- आयुक्त गढ़वाल/कुमायू मंडल, पौड़ी/नैनीताल।
- 4- समस्त जिलाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 5- मुख्य अभियन्ता, गढ़वाल/कुमायू क्षेत्र, लो०नि०वि०, पौड़ी/अल्मोड़ा।
- 6- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 7- वित्त अनुभाग-2/वित्त नियोजन प्रकोष्ठ, उत्तराखण्ड शासन।
- 8- बजट, राजकोषीय नियोजन एवं संसाधन निदेशालय उत्तराखण्ड शासन।
- 9- निदेशक राष्ट्रीय सूचना केन्द्र, उत्तराखण्ड देहरादून।
- 10- लोक निर्माण अनुभाग-1/3 उत्तराखण्ड शासन।
- 11- गार्ड बुक।

आज्ञा से,

(टी०के० पन्त)
संयुक्त सचिव।

प्रेषक,

इन्दु कुमार पाण्डे,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

समस्त प्रमुख सचिव/सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

2- समस्त विभागाध्यक्ष
उत्तराखण्ड।

सिंचाई विभाग।

देहरादून: दिनांक: 23 जनवरी, 2007

विषय:- सिंचाई अनुसंधान संस्थान रुड़की से मृदा/पदार्थ परीक्षण/जल विज्ञान
महोदय, शोध/प्रतिरूप परीक्षण एवं अन्य कार्य कराया जाना।

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि तत्कालीन मुख्य सचिव, उत्तरांचल शासन के हस्ताक्षर से निर्गत कार्यालय ज्ञाप संख्या-16 सी-1-सि/2001 दिनांक 03 फरवरी, 2001 के द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि "पूर्ववर्ती उत्तर प्रदेश राज्य में लोक निर्माण विभाग एवं अन्य अभियन्त्रण विभाग द्वारा मृदा परीक्षण एवं अन्य परीक्षण कार्य लखनऊ स्थित लोक निर्माण प्रयोगशाला आदि से कराये जाते थे। उत्तराखण्ड में सिंचाई विभाग के अंतर्गत सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की स्थापित है, जहाँ इस प्रकार के सभी परीक्षण की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अतः भविष्य में कृपया ऐसे परीक्षण कार्य अनुसंधान संस्थान, रुड़की से कराये"। ऐसा प्रतीत होता है कि अन्य किसी भी अभियन्त्रण विभाग द्वारा सिंचाई विभाग के अंतर्गत सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की का उपयोग उक्त कार्य हेतु नहीं किया जा रहा है। प्रसंगवश यहाँ यह उल्लेख करना भी उचित होगा कि उत्तराखण्ड राज्य की भौगोलिक स्थिति भूकम्पीय परिक्षेत्र के अंतर्गत आने के कारण यह क्षेत्र अत्यन्त संवेदनशील हो गया है, इसलिए यहाँ निर्माणाधीन व भविष्य में निर्माण होने वाले भवन, पुल, बांध आदि के निर्माण में उपयोग होने वाली समस्त निर्माण सामग्री यथा-सीमेन्ट, ईंट, बजरी, रेत, बालू, पत्थर आदि का उपयोग करने से पूर्व उसकी गुणवत्ता को निश्चित रूप से परीक्षण/जांच कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है अन्यथा निर्माण सामग्री विशिष्टियों के अनुरूप न होने के कारण धनजन की अपार हानि होने की सम्भावना बढ़ जायेगी।

अतः शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि उत्तराखण्ड राज्य के समस्त अभियन्त्रण विभागों के द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों की सामग्री विशेषकर मृदा परीक्षण एवं अन्य निर्माण सामग्री तथा निर्माण स्थल की उपयुक्तता का परीक्षण/जांच, सिंचाई विभाग के अंतर्गत अनुसंधान संस्थान रुड़की से निश्चित रूप से करा लिया जाय क्योंकि सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की में इस प्रकार के परीक्षण कार्य की सभी सुविधाएँ उपलब्ध हैं। अतएव अपार जनहित में यह सर्वथा उचित होगा कि कृपया निर्माण कार्यों में उपयोग की जाने वाली समस्त सामग्रियों का तकनीकी परीक्षण/जांच उक्त संस्थान से कराये जाने हेतु अपने अधीनस्थ अभियन्त्रण विभागों के अधिकारियों को कड़े निर्देश प्रदान करने का कष्ट करें।

इन्दु कुमार पाण्डे
अपर मुख्य सचिव

संख्या-5462/11-2007-13(04)/03/तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- निजी सचिव, मा0 राज्य मंत्री, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड को मा0 मंत्री जी के संज्ञानार्थ।
- 2- मुख्य अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, सिंचाई विभाग, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- मुख्य अभियन्ता, परिकल्प एवं निदेशक, सिंचाई अनुसंधान संस्थान, रुड़की को उनके पत्र दिनांक 28.10.2006 के क्रम में सूचनार्थ।
- ✓ 4- निदेशक, राष्ट्रीय सूचना केन्द्र सचिवालय परिसर, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- समस्त निर्माण एजेंसिया नगर निगम/नगर पालिका/विकास प्राधिकरण, उत्तराखण्ड।
- 6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,



(टीकम सिंह पंवार)
संयुक्त सचिव

प्रेषक:
डॉ० एम०सी० जोशी,
अपर सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,
निदेशक, उरेडा
देहरादून।

ऊर्जा विभाग:

देहरादून: दिनांक 25 जनवरी, 2007

विषय: वित्तीय वर्ष 2006-07 में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को वैकल्पिक ऊर्जा कार्यक्रम के लिये अनुदान की स्वीकृति।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या 3582/उरेडा/08(1)/राज्य/जि०यो०/06, दिनांक 11.11.2006 के संदर्भ में एवं शासनादेश सं० 1232/1/2006-03(1)/28/06, दिनांक 29.08.2006 के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में उत्तरांचल अक्षय ऊर्जा विकास अभिकरण (उरेडा) को जिला सेक्टर में रु० 3,41,000.00 की धनराशि संलग्न बी०एम०-15 के अनुसार पुनर्विनियोग के द्वारा तथा रु० 8,11,000.00 संगत मद से अर्थात् कुल रु० 11,52,000.00 (रु० ग्यारह लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि अनुदान के रूप में निम्न शर्तों के अधीन आहरित कर व्यय करने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

- 1- उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति द्वारा अनुमोदित कार्यों पर उनके लिये जनपदवार अनुमोदित परिव्यय की सीमा के अन्तर्गत ही किया जायेगा।
- 2- स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष जिन योजनाओं में भारत सरकार से धनराशि प्राप्त होती है, उसी प्राथमिकता के आधार पर प्राप्त कर योजनावार प्राप्त केन्द्रांश की सूचना शासन को उपलब्ध कराई जायेगी।
- 3- स्वीकृत धनराशि का बिल वित्त एवं लेखाधिकारी, उरेडा, देहरादून द्वारा तैयार कर सहायक विद्युत निरीक्षक, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित के उपरान्त देहरादून कोषागार से आवश्यकतानुसार ही धनराशि का आहरण किया जायेगा। तदोपरान्त निदेशक, उरेडा द्वारा सम्बन्धित जिलों को धनराशि प्रेषित की जायेगी एवं जनपदवार प्रेषित की गई धनराशि की सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।
- 4- व्यय करने से पूर्व बजट मैनुअल, फाईनैन्सियल हैण्डबुक, स्टोर परचेज मूल्य गितव्ययता टैण्डर के विषय में निर्गत आदेश एवं अन्य के सुसंगत नियमों का अनुपालन किया जायेगा, यदि कार्य पर स्वीकृति के पूर्व किसी तकनीकी स्वीकृति की आवश्यकता है, तो वे भी प्राप्त कर ही धनराशि व्यय की जायेगी।
- 5- स्वीकृत की जा रही धनराशि का मदवार व्यय विवरण व उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, उरेडा द्वारा शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जायेगा।
- 6- कार्य की समयबद्धता एवं गुणवत्ता हेतु सम्बन्धित जनपद के परियोजनाधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।
- 7- स्वीकृत की जा रही धनराशि का दिनांक: 31.3.2007 तक उपयोग सुनिश्चित कर लिया जायेगा और उक्त तिथि तक कार्यवार वित्तीय/भौतिक प्रगति का विवरण एवं उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध करा दिया जायेगा। समय से धनराशि का उपयोग न करने वाले प्रोजेक्ट मैनेजर/सक्षम अधिकारी का स्पष्टीकरण प्राप्त कर उसके विरुद्ध समुचित कार्यवाही की जायेगी।
- 8- जिला योजना में सामान्य/सब ट्राईबल प्लान के लिये धनराशि अलग से निर्गत की जायेगी।

9- स्वीकृत की जा रही धनराशि का कोषागार से आहरण तब ही किया जायेगा, जब वर्ष 2005-06 में लाभान्वित होने वाले परिवारों का विवरण समाज कल्याण नियोजन प्रकोष्ठ को उपलब्ध करा दिया जायेगा।

10- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-30 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक 2810-वैकल्पिक ऊर्जा-आयोजनागत की संलग्नक में उल्लिखित सुसंगत मानक मदों के नामों डाला जायेगा।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या- 498/XXXVII(2)/2006, दिनांक 22 दिसम्बर, 2006 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।
संलग्न- यथोक्त।

भवदीय

/

(डॉ० एम०सी० जोशी)
अपर सचिव

संख्या:- ⁵⁹⁹ /1/2007-03(1)/28/06, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- स्टाफ ऑफिसर-मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड।
- 3- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 4- कोषाधिकारी, देहरादून।
- 5- सचिव, मुख्यमंत्री को मा० मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
- 6- निजी सचिव, ऊर्जा मंत्री को मा० ऊर्जा राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।
- 7- सहायक विद्युत निरीक्षक, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
- ✓ 8- प्रभारी, एन.आई.सी. सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- नियोजन विभाग/वित्त अनुभाग-2
- 10- विभागीय आदेश पुस्तिका हेतु।

आज्ञा से,



(एम०एम० सेमवाल)

अनु सचिव

शासनादेश सं० 599 /1/2007-3(1)/28/2006, दिनांक 25 जनवरी, 2007 का संलग्नक

अनुदान सं० 30

क्र०सं०	लेखाशीर्षक	धनराशि
1-	2810-वैकल्पिक ऊर्जा-02-सोलर एनर्जी-आयोजनागत-101-सोलर थर्मल कार्यक्रम-02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-91-सोलर एनर्जी कार्यक्रम हेतु उरेडा को अनुदान (जिला योजना)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	3.60
2-	102-सोलर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम-02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-आयोजनागत-91-सोलर फोटो उरेडा के लिए अनुदान (जिला योजना)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	7.62
3-	60-ऊर्जा के अन्य स्रोत-800-अन्य-02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान-95-ग्रामीण ऊर्जा तकनीकी हेतु उरेडा को अनुदान (जिला योजना)-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता	0.30
	योग:-	11.52

(रु० ग्यारह लाख बावन हजार मात्र)



(डॉ० एम०सी० जोशी)

अपर सचिव



बै0एन0-15

पुनर्विनियोग 2006-2007 आयोजनागत अनुदान सं0-30
नियन्त्रक अधिकारी-प्रमुख सचिव-ऊर्जा विभाग

(सू) हजार

बजट प्राविधान तथा लेखाश्रीवर्क का विवरण	मानक मदवार अध्यावधि क व्यय	वित्तीय वर्ष के शेष अवधि में अनुमानित व्यय	अवशेष सरलत धनराशि	लेखाश्रीवर्क जिसमें धनराशि स्थानान्तरित किया जाना है।	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 5 की कुल धनराशि	पुनर्विनियोग के बाद स्तम्भ 1 में कुल अवशेष धनराशि	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5	6	7	8
2810-वैकल्पिक ऊर्जा 02-सोलर एनर्जी-आयोजनागत 102-सोलर फोटोवोल्टाइक कार्यक्रम 02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पौनेन्ट प्लान-आयोजनागत 91-सोलर फोटो चरखा के लिए अनुदान (जिला योजना) 20-सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	9562 8420 801	801	341(के) 341	2810-वैकल्पिक ऊर्जा 02-सोलर एनर्जी-आयोजनागत 101-सोलर थर्मल कार्यक्रम 02-अनुसूचित जातियों के लिए स्पेशल कम्पौनेन्ट प्लान 91-सोलर एनर्जी कार्यक्रम हेतु चरखा को अनुदान (जिला योजना) 20-सहायक अनुदान / अंशदान / राज सहायता	341 (ख) 610	9221 9221	(क) आग्रयक होने के कारण (ख) प्लान अ के अनुसार बजट व्यवस्था के कारण।
प्रमाणित किया जाता है कि पुनर्विनियोग से बजट में कुल के परिच्छेद-150,151,155,156 में उल्लिखित सामग्रों का एवं प्राविधानों का उल्लंघन नहीं होता है।	9562 8420 801	801	341 341		341 (ख) 610	9221 9221	

(डॉ० एम०सी० जोशी)

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
वित्त अनुभाग-2

संख्या: 498(के)/XXVII-2/06
देहरादून दिनांक: 22 दिसम्बर, 2006

पुनर्विनियोग स्वीकृत

टी.एन. सिंह
अपर सचिव

संख्या: 599 /N/2007-03(1)/28/06 दिनांक 25 जनवरी, 2007

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनाार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

- 1- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 2- वित्त अनुभाग-2

(डॉ० एम०सी० जोशी)

अपर सचिव

उत्तराखण्ड शासन
चिकित्सा अनुभाग-2
संख्या : 01 /अट्ठाईस-2-2007-190/2007
देहरादून: दिनांक 25 जनवरी, 2007

कार्यालय ज्ञाप

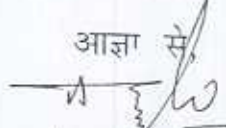
एतद्वारा श्री राज्यपाल महोदय डा0 आर0सी0आर्या, सेवानिवृत्त महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को शासनादेश सं0 स1-4-392/दस-99-203-86, दिनांक 01 जुलाई 1999 के अन्तर्गत उनके स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के दिनांक 15.12.2006 को उनके अवकाश लेखे में अर्जित 300 दिन के उपार्जित अवकाश के नकदीकरण की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं। डा0 आर्या के अवकाश लेखे में जमा अर्जित अवकाश के लिये नियमानुसार अनुमन्य अवकाश वेतन और (सेवानिवृत्त के दिनांक को मंहगाई भत्ता की प्रभावी दरों के अनुसार उस अवकाश वेतन पर प्राप्त होने वाले) मंहगाई भत्ते के योग के बराबर की धनराशि प्राप्त होगी। उक्त अवकाश नकदीकरण में डा0 आर्या को पर्वतीय भत्ता/नगर प्रतिकर भत्ता/मकान किराया भत्ता आदि देय नहीं होंगे।

मंजुल कुमार जोशी
अपर सचिव

संख्या : 01 ()/अट्ठाईस-2-2007-190/2007, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 2- महानिदेशक, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- सम्बन्धित सेवानिवृत्त अधिकारी द्वारा महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
- 5- गार्ड फाईल/एन0आईसी0।

आज्ञा से

(अतर सिंह)
उप सचिव।

प्रेषक,

आर०डी०पालीवाल,
सचिव एवं विधि परामर्शी,
उत्तराखण्ड शासन ।

सेवा में,

महाधिवक्ता, उत्तराखण्ड,
नैनीताल ।

न्याय अनुभाग : 2

देहरादून : दिनांक : २५ जनवरी, 2007

विषय:- वित्तीय वर्ष 2006-2007 के लिए धनराशि की स्वीकृति ।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या 215/2005-06, दिनांक 11.12.2006 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें ।

2. इस सम्बन्ध में शासनादेश संख्या: 3-दो(6)/XXXVI(1)/2006-1-दो(6)/06, दिनांक 11.5.2006 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2006-07 में मद संख्या-08-कार्यालय व्यय में रुपये 60,000/- (रुपये साठ हजार मात्र) की अतिरिक्त धनराशि को व्यय किये जाने स्वीकृति निम्न शर्तों के अधीन महामहिम राज्यपाल सहर्ष प्रदान करते हैं :-

- (1) कृपया प्रत्येक माह होने वाले व्यय की सूचना प्रपत्र बी0एम0-13 के माध्यम से विलम्बतम 20 तारीख तक उपलब्ध कराने का कष्ट करें ।
- (2) उपर्युक्त धनराशि बजट मैनुअल, वित्त हस्त पुस्तिका के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत शासकीय अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति की आवश्यकता हो, उनमें व्यय करने से पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाय ।
- (3) उपर्युक्त सुसंगत मद में अंकित धनराशि से अधिक व्यय किसी भी दशा में न किया जाय ।

3. इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय वर्तमान वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-04 के अन्तर्गत लेखा शीर्षक "2014-न्याय प्रशासन-00-आयोजनेत्तर-114-विधि सलाहकार और परामर्शदाता(काउन्सिल)-03-महाधिवक्ता-00-08-कार्यालय व्यय के नामें डाला जायेगा ।

4. यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या यू०ओ० 30/XXVII(5)/2007, दिनांक 18.1.07 में प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं ।

भवदीय,

(आर०डी०पालीवाल)

सचिव ।

संख्या : 7-दो(6)/XXXVI(1)/2006-1-दो(6)/06-तदुदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड, माजरा, देहरादून ।
- 2- वरिष्ठ कोषाधिकारी, नैनीताल ।
- 3- वित्त अनुभाग-5, उत्तराखण्ड शासन ।
- 4- ✓ एन०आई०सी०/सम्बन्धित सहायक/गार्ड बुक ।

अग्र से,

(आलोक कुमार वर्मा)

अपर सचिव ।

खेल निदेशालय, उत्तराखण्ड,
देहरादून।

संख्या 4799 / प्र.क्री.सं.अनु.प. / 2006-2007 / दे.दून दिनांक 25 जनवरी, 2007


जिला क्रीड़ा अधिकारी,
देहरादून।

विषय:- प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों आदि को प्रतियोगिता के आयोजन हेतु धनराशि उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में।

चालू वित्तीय वर्ष 2006-2007 के अनुदान संख्या-11 के लेखाशीर्षक 2204-खेलकूद तथा युवा सेवाएं-104-खेलकूद "12-प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों को प्रतियोगिता आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान-20-सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता" मद आयोजनेत्तर में शासनादेश संख्या-16/VI-I/2007-2 (दो) 2005 दिनांक 19 जनवरी, 2007 द्वारा पुनर्विनियोग के माध्यम से खेल निदेशालय को उपलब्ध करायी गयी रु. 5.00 लाख (रु. पांच लाख मात्र) की धनराशि आवंटित की जाती है।

अध्यक्ष, उत्तरांचल स्टेट बैडमिन्टन एसोसियेशन द्वारा किये गये अनुरोध पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि दिनांक 31 जनवरी, 2007 से 04 फरवरी, 2007 तक देहरादून में आयोजित हो रही आल इंडिया मेजर रैंकिंग प्राइज मनी बैडमिन्टन टूर्नामेंट के आयोजन हेतु उक्त मद से रु. 5.00 लाख की धनराशि आहरित कर अनुदान स्वरूप दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अतः आप "12-प्रदेशीय क्रीड़ा संघों, क्लबों एवं अन्य क्रीड़ा संघों को प्रतियोगिता आयोजन करने एवं खेलकूद उपस्कर क्रय हेतु अनावर्तक अनुदान-20-सहायक अनुदान/अशंदान/राज सहायता" मद आयोजनेत्तर में आवंटित रु. 5.00 लाख की धनराशि आहरित कर अध्यक्ष, उत्तरांचल स्टेट बैडमिन्टन एसोसियेशन, देहरादून को उपलब्ध करायें।



(अमिताभ श्रीवास्तव)
निदेशक खेल

उत्तराखण्ड शासन
ऊर्जा विभाग
संख्या: 555/1/2007-02(3)/11/2003,
देहरादून: दिनांक: 24 जनवरी, 2007

अधिसूचना

अधिसूचना संख्या 75/1/2004-02(3)/11/2003, दिनांक 01.11.2004 का अधिकरण करते हुए विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 135 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके उक्त धारा के अधीन जांच/कार्रवाई हेतु निम्नलिखित अधिकारियों को प्राधिकृत किए जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

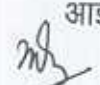
- 1- उत्तरांचल पावर कारपोरेशन के सहायक अभियन्ता/उपखण्ड अधिकारी व उससे उच्च स्तर के अधिकारी।
- 2- उत्तरांचल पावर कारपोरेशन के पुलिस सतर्कता शाखा में तैनात पुलिस उपाधीक्षक व उससे उच्च स्तर के अधिकारी।

आज्ञा से,

(इन्दु कुमार पण्डे)
अपर मुख्य सचिव

संख्या: 555/1/2007-02(3)/11/2003, तदिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महानिरीक्षक, उत्तराखण्ड।
- 2- समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
- 3- सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, उत्तराखण्ड।
- 4- अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0, देहरादून।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि0, देहरादून।
- 6- प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि0, देहरादून।
- 7- पुलिस उपाधीक्षक, सतर्कता शाखा, यूपीसीएल, देहरादून।
- 8- प्रभारी, एन0आई0सी0, सचिवालय परिसर, देहरादून।
- 9- निदेशक, राजकीय फोटो लिथो प्रेस, रुड़की (हरिद्वार) को अंग्रेजी अनुवाद की प्रति सहित इस अनुरोध के साथ प्रेषित है कि अधिसूचना को गजट के आगामी अंक में प्रकाशन कर 50 प्रतियां शासन को उपलब्ध करायी जायें।
- 10- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(डा0 एम0सी0 जोशी)
अपर सचिव

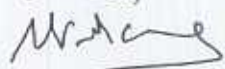
In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification No. 555/I/2007-02(3)/11/03, dated 24 January, 2007 for general information.

GOVERNMENT OF UTTARAKHAND
DEPARTMENT OF POWER
NO. 555/I/2007-02(3)/11/03
Dehradun: Dated: 24 January, 2007

NOTIFICATION

In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 135 of the Electricity Act, 2003, the Governor is pleased to authorize following officers for investigate/take action under the said section by supersession of notification no. 75/I/2004-02(3)/11/2003, dated: 01.11.2004:-

- 1- Assistance Engineer/Sub-divisional officer or officers higher than these in the Uttaranchal Power Corporation Ltd.
- 2- Deputy SP and officer higher than this posted in Police Vigilance Section in the Uttaranchal Power Corporation Ltd.

By order,

(Indu Kumar Pande)
Additional Chief Secretary

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग-5

संख्या-1277/XX(5)/06-169स्व0सं0से0/05

देहरादून: दिनांक 15 जनवरी, 2007

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि श्री डूंगर सिंह बिष्ट, मा0 उपाध्यक्ष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिषद द्वारा पदीय कर्तव्यार्थ सरकारी वाहन संख्या- यू0ए0-07एन/0572 को चलाने के लिए अपने स्तर से वाहन चालक के पद पर माह नवम्बर, 2006 में श्री बिलाल अली पुत्र स्व0 मो0 हुसैन को नियुक्त कर उन्हें रु0-5000/- भुगतान किया गया है तथा माह दिसम्बर, 2006 में श्री हरीश शर्मा पुत्र स्व0 भगवान दास शर्मा को नियुक्त कर उन्हें रु0-4600/- का भुगतान किया गया है। अतः श्री राज्यपाल महोदय विशेष परिस्थिति में उक्त कुल धनराशि रु0-9600/- (रुपये नौ हजार छः सौ मात्र) की प्रतिपूर्ति का भुगतान श्री डूंगर सिंह बिष्ट, मा0 उपाध्यक्ष को किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-“2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें-00- आयोजनेत्तर-092-अन्य कार्यालय-06-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिषद” की मानक मद 42-अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

एस0एस0टोलिया

अनु सचिव।

संख्या-1277 (1)/XX(5)/06-169स्व0सं0से0/05, तदिदनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- वित्त अधिकारी, लेखा विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को 2 अतिरिक्त प्रतियों में।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- श्री डूंगर सिंह बिष्ट, मा0 उपाध्यक्ष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिषद।
- 5- गार्ड फाईल।
- 6- एन.आई0सी., सचिवालय परिसर।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)

अनु सचिव।

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग-5

संख्या-1275/XX(5)/06-169स्व0सं0से0/05

देहरादून: दिनांक 15 जनवरी, 2007

कार्यालय ज्ञाप

अधोहस्ताक्षरी को यह कहने का निदेश हुआ है कि गोपन विभाग के कार्यालय ज्ञाप संख्या-867/29/1/3/XXI/2005सी.एक्स, दिनांक 23-11-2005 के अन्तर्गत श्री डूंगर सिंह बिष्ट, मा0 उपाध्यक्ष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिषद द्वारा अपने स्तर से उन्हें आवंटित सरकारी वाहन संख्या-यू0ए0-07एन/0572 हेतु कय किये गये पेट्रोल व्यय, माह नवम्बर, 2006 में 150 लीटर रू0-7294/- एवं दिसम्बर, 2006 में 150 लीटर रू0-6969/- अर्थात्, कुल धनराशि रू0-14263/- (रूपये चौदह हजार दो सौ तिरसठ मात्र) की प्रतिपूर्ति का भुगतान श्री डूंगर सिंह बिष्ट, मा0 उपाध्यक्ष को किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2006-2007 के आय-व्यय के अनुदान संख्या-15 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक-"2251-सचिवालय सामाजिक सेवायें-00-आयोजनेत्तर-092-अन्य कार्यालय-06-स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिषद" की मानक मद 15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल खरीद के नामे डाला जायेगा।

एस0एस0टोलिया

अनु सचिव।

संख्या-1275(1)/XX(5)/06-169स्व0सं0से0/05, तदिदिनांक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार, उत्तराखण्ड, ओबेराय मोटर्स बिल्डिंग, माजरा, देहरादून।
- 2- वित्त अधिकारी, लेखा विभाग, सचिवालय प्रशासन विभाग, उत्तराखण्ड शासन को उपरोक्त मूल बीजकों सहित 2 अतिरिक्त प्रतियों में।
- 3- वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
- 4- श्री डूंगर सिंह बिष्ट, मा0 उपाध्यक्ष, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी एवं उत्तराधिकारी कल्याण परिषद।
- 5- गार्ड फाईल।
- 6- एन.आई0सी, सचिवालय परिसर।

आज्ञा से,

(एस0एस0टोलिया)

अनु सचिव।

संख्या :- 547 /1/2006-05/34/2003

प्रेषक :

डॉ० एम०सी० जोशी,
अपर सचिव (ऊर्जा),
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

1. अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन लि०,
देहरादून।
2. प्रबन्ध निदेशक,
पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि०,
देहरादून।
3. प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि०,
देहरादून।

ऊर्जा विभाग :

विषय :-

देहरादून : दिनांक : 24 जनवरी, 2007

उत्तरांचल पावर कॉरपोरेशन लि०, पावर ट्रांसमिशन कॉरपोरेशन ऑफ उत्तरांचल लि०
एवं उत्तरांचल जल विद्युत निगम लि० के निदेशक मण्डल में अंशकालिक निदेशक
नामित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक के सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेशक हुआ है कि श्री इन्दु कुमार पाण्डे, तत्कालीन प्रमुख सचिव, वित्त के स्थान पर श्री आलोक कुमार जैन, प्रमुख सचिव, वित्त को उक्त निगमों में शासन के प्रतिनिधि के रूप में अंशकालिक निदेशक नामित करने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त भविष्य में जब भी वित्त विभाग का कार्यभार नये प्रमुख सचिव द्वारा ग्रहण किया जायेगा तो वे स्वतः ही उक्त निगमों में शासन के प्रतिनिधि के रूप में अंशकालिक निदेशक नामित रहेंगे।

भवदीय,



(डॉ० एम०सी० जोशी)

संख्या : 547 /1/2006-05/34/2003, तददिनांक

